भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 280
उत्तर देने की तारीख 27 **नवम्बर**, 2024

अन्तरिक्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी

280. **श्री मनीश तिवारी:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के लिए नीलामी को अनिवार्य करने वाले 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए प्रतिस्पर्धी नीलामियों के बजाय अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन का विकल्प चुना है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने स्थलीय स्पेक्ट्रम के विपरीत इसे नीलाम करने के बजाय प्रशासनिक रूप से अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम आवंटित करने से संभावित राजस्व हानि या लाभ का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी को आगे न बढ़ाने का कोई औचित्य है; और
(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि प्रशासनिक रूप से अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम आवंटित करने से पुरानी कंपनियों की तुलना में नई कंपनियों के लिए अनुचित लागत लाभ पैदा नहीं होता है, जिन्होंने उच्च नीलामी कीमतों पर स्थलीय स्पेक्ट्रम खरीदा है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) दूरसंचार अधिनियम, 2023 में सेवाओं जिनमें कतिपय अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं शामिल हैं, के लिए अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम को सौंपने का प्रावधान है। प्रथम अनुसूची में अधिनियम की धारा 4(5) (क) में सूचीबद्ध कारणों के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। ऐसा जनहित में या सरकारी कार्यों को करने के लिए या जहां तकनीकी या आर्थिक कारणों से स्पेक्ट्रम की नीलामी स्पेक्ट्रम को सौंपने का प्राथमिक तरीका न हो वहाँ किया जा सकता है।

इसके अलावा प्रशासनिक रूप से या नीलामी के माध्यम से सौंपे गए स्पेक्ट्रम पर प्रभार लगाया जाता है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अनुरूप दूरसंचार विभाग ने स्थलीय अभिगम सेवाओं के साथ समान अवसर प्रदान करते हुए सेटेलाइट आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक लाइसेंसधारकों के संबंध में स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण सहित स्पेक्ट्रम को सौंपने के लिए निबंधन और शर्तों के संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से सिफारिशें मांगी हैं। ट्राई द्वारा दूरसंचार विभाग को सिफारिशें अभी उपलब्ध कराई जानी हैं।

*****